कि अन्तिम रूप से बिल नहीं लाते, तब तक कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों को देंगे जिससे कि इन बागान मजदूरों को कुछ राहत मिल सके ? बागान मजदूरों का सब से अधिक शोषण किया जाता है और किसी क्षेत्र में ऐसा शोषण नहीं होता है । उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है, उनके रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है । वे जो काम करते हैं उनमें से 25 परसेंट पत्तियां काट ली जाती हैं और उन्हें उसकी मजदूरी नहीं दी जाती है । उन पत्तियों पर लेवल लगा कर कम्पनी वाले बेचते हैं । क्या इसको रोकने की भी आप व्यवस्था करेंगे ?

SHRI RAVINDRA VARMA: The hon. Member has drawn attention to various malpractices in the plantations and the hardships that the plantation workers are encountering today The Plantation Act was meant to deal with these problems But in the light of experience it has been found necessary to make the provisions of the Act more comprehensive and more stringent. (*Interruptions*) He is anxious to know two things, whether the Government will issue instructions to the State Governments to ensure that the provisions of the Act are enforced and when the new Bill will be introduced. On the first point there is a constant attempt to draw the attention of all the State Governments to the powers that they already enjoy and the obligations that are cast on the plantations. On the second, I would say that it is our hope that it will be possible for us to introduce the Bill without much further delay.

श्री हुकम चंद नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मैनेजर मजदूरों के साथ अपराध करते हैं या किसी तरह की गड़बड़ करते हैं उनके लिए जो आर्थिक दंड की व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं है । मैनेजर, मालिक आदि आर्थिक दण्ड दे कर अपना काम निपटा लेते हैं । इसके बदले क्या सरकार कानून में यह प्रावधान करना चाहती है या नहीं कि मजदूर के हितों के साथ कोई मैनेजर या मालिक खिलवाड़ करे तो उसको सश्रम कारावास की सजा दी जाए ? जब तक उनके वास्ते जेल की व्यवस्था नहीं होगी कदाचारी जो लोग हैं वे मजदूरों का शोषण करते रहेंगे ? ऐसा सरकार का करने का विचार है या नहीं ?

बागान आदि में बिहार वासियों को खदेड़ने का काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार कुछ व्यवस्था करना चाहती है या नहीं ?

SHRI RAVINDRA VARMA: One of the demands that has been constantly made is that the present provisions in the Act should be made more deterrent and the suggestion has been that instead of the present provision which is largely the provision of alternative penalties, fine or imprisonment, a term of imprisonment must be made compulsory for those who violate or infringe the provisions of the Act. The Government at the moment is proposing to introduce a clause in the Bill which would provide for compulsory imprisonment in certain cases

मुरैना रेलवे स्टेशन पर उपरी-पुल

*444. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना रेलवे स्टेशन पर रेलवे फाटक पर उपरी-पुल के निर्माण हेतु रेलवे के बजट में लगातार 1966 से उपबन्ध किया जा रहा है,

(ख) मुरैना रेलवे फाटक पर उपरि-पुल के न होने के कारण वहां पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुई ,

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार से रेलवे द्वारा अनुरोध किया गया था कि वह उपरि-पुल के निर्माण के लिए धनराशि में अपना हिस्सा दे और क्या वह इस के लिए सहमत हो गई है , और

(घ) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) राज्य सरकार ने रेलवे को सूचित किया है कि धन की कमी है, इसलिए इस कार्य को स्थगित रखा जाये ।

श्री छवि राम अर्गल : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह निराधार है और असत्य है । मुरैना रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए सन् 66 से रेलवे के बजट में प्रावधान है । मंत्री महोदय बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने यह कहा है कि हमारे पास धनाभाव है और इस कारण से हम अपने हिस्से की राशि देने के लिए तैयार नहीं हैं । मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है कि मुरैना की नगरपालिका ने 16 लाख रुपया देने का प्रस्ताव किया है और राज्य सरकार भी अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है । मंत्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं कि राज्य सरकार ने कहा है कि उसके पास धनाभाव है । सदन में असत्य जानकारी देना ठीक नहीं है । उनके पास पूरी जानकारी नहीं है तो वह पूरी जानकारी मंगा लें ।

श्री शिव नारायण : उन्होंने कहा है कि झूठ है निराधार है । प्रोसीडिंग्ज सब मेरे पास हैं (व्यवधान) सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र ये लोग आए हैं ।

MR SPEAKER: You have said that Madhya Pradesh Government wanted to drop it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The hon Minister has used the word 'Harishchandra' for the Members...
(Interruptions)

MR SPEAKER: 'Harishchandra' is not an unparliamentary word.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स का ऐक्सपर्ट हूं । अगर इनको सवाल का जवाब नहीं लेना है तो मैं क्या करूं ? . . .

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Don't get excited. Keep cool.

श्री शिव नारायण : ओवरब्रिज का जो प्रश्न है पहले . . . . . *(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Please answer the question. Don't get bogged down.

श्री शिव नारायण : इस ओवरब्रिज की पहले अलग से मांग की थी स्टेट गवर्नमेंट ने । आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिये और आधा हमको । तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन कराया । अब कह रहे हैं कि हमारा उसी जगह पर ऊपर से बना दीजिये । . . .

श्री छविराम अर्गल : आप बिलकुल गलत कहते हैं ।

श्री शिव नारायण : हमारे पास डाकूमेन्ट्स हैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट है । अगर आप परमिट करें तो मैं उसको पढ़ दूं :

"As per the extant rules, proposals for the construction of road over/under-bridges should be sponsored by the State Government *(Interruptions)*

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में ।

श्री शिव नारायण : चुप रहो हिन्दी वाले । . . .
(व्यवधान)

MR SPEAKER: Don't record
*(Interruptions)***

SHRI SHEO NARAIN: I wanted to read it It says:

"As per the extant rules, proposals for the construction of road over/under-bridges should be sponsored by the State Government/ Local Authority with an undertaking to bear their share of cost. For the road over/under-bridges required to be constructed in replacement of the existing level crossing (constructed originally at Railways' cost), the cost is shared broadly on 50:50 basis between the State Government/Local Authority and the Railways. For the new road over/ under-bridges (not in replacement

**Not recorded.

the existing level crossings), the entire cost (both initial and recurring) is to be borne by the State Government/Local Authority It is the policy of the Railways to encourage construction of road over/under-bridges in replacement of busy level crossings so as to avoid accidents and traffic detention thereon Moreover a Railway Safety Works Fund has been constituted with effect from 1-4-1966 to assist the State Governments who can get reimbursement of their share of cost of safety works like road over/under-bridges in replacement of level crossings from this Fund "

चूंकि इन्होंने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि प्रोसीडिंग पढ़ लें

MR SPEAKER Question Hour is now over

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Transfer Policy in D G M S

*428 SHRI ROBIN SEN Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be leased to state

(a) whether he is aware that in the Director-General of Mines Safety Department there is no agreed or standing staff transfer policy as a result of which the question of frequent indiscriminate staff transfers through out India has become a life and death matter of the employees and

(b) if so the steps proposed to be taken in this matter?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) (a) and (b) There is a general policy on transfer of employees of the Directorate General of Mines Safety Recently this has been reviewed in consultation with the representatives of the employees association While transfers are generally made within the agreed framework, exceptions have to be made to meet the requirements of administrative convenience, discipine and public interest

Sealdah-Bongaon Line

*433 SHRI CHITTA BASU Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the stage at which the project of doubling the Railway track between Sealdah and Bongaon of the Eastern Railway which was reported to have been included in the Works programme for the year 1979-80 rests now and the full facts in respect of this project?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF MADHU DANDAVATE) The section Sealdah to Dum Dum has already four tracks Doubling of Dum Dum-Barasat section has been included in the 1979-80 Budget along with conversion of three flag stations to crossing station and other signalling improvements on Habra-Bongaon section The work on this Rs 7 77 crore project will start in the next financial year

Offer to containerise Ports

*434 SHRI JANARDHANA POOJARY
DR P V PERIASAMY

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state

(a) whether Saudi Arabian firm has offered to containerise Bombay, Cochin and Kandla Ports and

(b) if so the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) (a) and (b) In August, 1978, Bombay Port Trust entered into an Agreement with M/s Marine Transport International (Bermuda) Ltd, a wholly owned subsidiary of a Saudi Arabian firm for providing